



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
बड़कोट (उत्तरकाशी)।



Website- <http://pwd.uk.gov.in>

e-mail:- eenhpwdbarkot@gmail.com

दूरभाष/फैक्स नं० 01375-224428

पत्रांक 551/०५/भू०अ०

दिनांक 28/05/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- चार घाम परियोजना (ऑल वेदर रोड) के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-94 (134) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 24.300 (घरासू बैण्ड से सिलक्यारा बैण्ड) तक दो लेन चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त डंपिंग स्थल एवं लैण्ड स्लाईड जोन के उपचार के लिए 5.969 है० वन भूमि प्रस्ताव में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/36902/2018)

सन्दर्भ:- आपका पत्र सं०- 9422/12-1, दिनांक-26.05.2020 एवं वन संरक्षक भागीरथी वृत्त मुनिकिरेती का पत्रांक -1734/12-1, दिनांक-22.05.2020 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में आपको अवगत कराना है कि HPC (हाई पावर कमेटी) द्वारा परियोजना का निरीक्षण किया गया था, परन्तु वर्तमान तक उक्त प्रभाग की निरीक्षण आख्या प्राप्त नहीं हो पायी है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक -13.11.2019 में अंकित मा० उच्च न्यायालय के निर्देश पैरा-III, IV, के अनुसार On Going परियोजनाओं को ही स्वीकृति प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया जा सकता है, एवं जिन परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उनको HPC (हाई पावर कमेटी) द्वारा Review किया जाना है। तत्कम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक -13.11.2019 में अंकित मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार On Going परियोजना हेतु भूस्खलन उपचार एवं मक डिस्पोजल हेतु अतिरिक्त डंपिंग जोन का उक्त प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार On Going परियोजना के प्रस्ताव को पुनः आनलाईन स्वीकृति हेतु प्रेषित करने की कृपा करें। जिससे उक्त गतिमान परियोजना के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक -13.11.2019।

अधिशासी अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो०नि०वि०,
बड़कोट (उत्तरकाशी)

संख्या No. 10-2/2018-आर ओ एच क्यू

भारत सरकार / Government of India

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / Ministry of Environment, Forest & Climate Change

आर ओ एच क्यू / ROHQ

Indira Paryavaran Bhawan

Jor Bagh Road, Aliganj

New Delhi - 110003

Dated: 13th November, 2019

To,

The DDGF (Central),

Regional Office (NCZ), Dehradun

Sub: Clarification required by Regional Office (NCZ), Dehradun to consider forest land diversion proposals related to the Chardham Project in the light of the decision dated 08.08.2019 passed by Hon'ble Supreme Court in M.A. No. 2678-2680 of 2018 in C.A. No(s). 8518-8520 of 2018 - regarding.

Sir,

I am directed to refer to Regional Office (NCZ), Dehradun's letter dated 16.09.2019 wherein it is requested to issue directions whether to accord Stage-I/Stage-II approvals for the diversion proposals under FCA, 1980 which are not 'on-going'.

2. The matter has been examined in consultation with Legal Monitoring Cell in the Ministry and it is informed that Hon'ble Supreme Court in **para III and IV** of the order dated 08.08.2019 *inter-alia* directed as below:

III. The HPC shall identify the sites in which work (i.e. hill-cutting) has started and the stretches in which the work has not yet started. As far as the sites in which work has started, the High Powered Committee should recommend the measures which are required for stabilizing the area where hill-cutting has taken place, among others, the environmentally safe disposal of muck which has been generated so that it does not adversely affect the flora and fauna of the catchment area of the river

IV. As regards the stretches where work has not started, the HPC will review the proposed project and recommend measures which will minimize the adverse impact on environment, social life and bring the project in conformity with the steep valley terrain, carrying capacity, thus avoiding any triggering of new landslides and ensuring conservation and protection of sensitive Himalayan valleys.

3. It may be clearly noted from above para that Hon'ble Court has directed High Powered Committee (HPC) to identify the sites where work (i.e. hill cutting) has been started and the stretches in which work has not been started and the remedial measures to be taken accordingly. So, Regional Office (NCZ), Dehradun has to follow the instructions/orders of HPC in this regard.

3. As per the Ministry's understanding, a project is called "on-going" only if any trees have been felled and/or ground has been broken; in other words, if any non-forestry activity has been started on the ground. Any clarification relating to the said order may be sought by the necessary party i.e. MoRT&H directly from the Hon'ble Supreme Court, if required.

Yours faithfully,

(Signature of Shri. Anil Kumar Verma)
Deputy Inspector General of Forests
Tel: 011-24695323
E-mail: kr099@ifs.nic.in

T.O. (S.G.)